304

संख्या– /IV-3/2015–04(64)/2015

प्रेषक,

डी०एस० गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
अर्द्ध कुम्भ मेला–2016,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांकः 20 अक्टूबर, 2015

विषय– अर्द्ध कुम्भ मेला 2016 के अर्न्तगत सीतापुर–जमालपुर कलां जियापोता मार्ग का बी0सी0 द्वारा नवीनीकरण के कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–350/अ0कु0मे0/ लो0नि0वि0/ सीतापुर, जियापोता मार्ग, दिनांक 21.07.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि अर्द्ध कुम्भ मेला 2016 के अर्न्तगत सीतापुर–जमालपुर कलां जियापोता मार्ग का बी0सी0 द्वारा नवीनीकरण के कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये आगणन के सापेक्ष धनराशि रू0 199.46 लाख के कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए समस्त धनराशि रू0 199.46 लाख भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(i) भारत सरकार से प्राप्त धनराशि की प्रथम किश्त से ही उक्त धनराशि का समायोजन सुनिश्चित करेंगे।

(ii) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(iii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(iv) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि की स्वीकृति गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(v) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

(vi) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(vii) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(viii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(ix) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व करा लिया गया है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय व कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण किया जाय।

(x) निर्माण कार्य का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा तथा कार्य की थर्ड पार्टी क्वालिटी चैकिंग कराई जाएगी।

(xi) आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगी।

(xii) अस्वीकृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाएगी। साथ ही यह परिवर्तन स्वीकृत धनराशि की सीमान्तर्गत ही किया जाएगा।

(xiii) प्रश्नगत कार्य का गहन निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण लोक निर्माण विभाग के स्तर से भी किया जाएगा।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, वित्तीय हस्त पुस्तिका व बजट मैनुअल के अनुसार किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 की अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4217– शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01 केन्द्रीय आयोजनगत/केन्द्रपुरोनिधानित–0107–अर्द्ध कुम्भ मेला, 2016 की मानक मद संख्या–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–540/XXVII(2)/15, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5– एलॉटमैण्ट आई0डी0 संख्या–एस01510130187 एवं एच01510131372 दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के द्वारा उक्त धनराशि ऑनलाइन रूप से अवमुक्त की गई है।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या– 1237/IV-3/2015–04(64)/2015, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी0–1/105, इन्दरा नगर, देहरादून।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. मेलाधिकारी, हरिद्वार।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
9. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
11. वित्त अनुभाग–2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रईस अहमद)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, Urban Development (S054)

आवंटन पत्र संख्या - **1237/15-04(64)2015**

अनुदान संख्या - **013**

अलोटमेंट आई डी - **S1510130187**

आवंटन पत्र दिनांक -19-Oct-2015

HOD Name - Secretary, Urban Development (Grants) (9005)

1: **लेखा शीर्षक**

4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

07 - अर्धकुम्भ मेला, 2016

03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन	1611725000	19946000	1631671000
	1611725000	**19946000**	**1631671000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 19946000

(विशेष अनुभाग)
अपर सचिव,
शहरी विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, Urban Development (Grants) (9005)

आवंटन पत्र संख्या - **1237/15-04(64)2015**

अनुदान संख्या - **013**

अलोटमेंट आई डी - **H1510131372**

आवंटन पत्र दिनांक -19-Oct-2015

DDO Name - Meladhikari KumbhHaridwar (2871) , Treasury - Haridwar (6500)

1: **लेखा शीर्षक** 4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

800 - अन्य व्यय

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित

07 - अर्धकुम्भ मेला, 2016

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन	1546345000	19946000	1566291000
	1546345000	**19946000**	**1566291000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 19946000

(राजीव अग्रवाल)
अनु सचिव,
शहरी विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन।